लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

2022

नई उमंग है नया सवेरा,
नव वर्ष अभिनन्दन तुम्हारा

पाक्षिक 1-15 जनवरी 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -33

आयुष, लौटता भरोसा-बढ़ते कदम 3

नौकरियों में प्रतिभाओं को मिल रहा सम्मान 6

देसी खाणा, देसी बाणा, इसा म्हारा हरियाणा 8

सुशासन पारदर्शिता का संकल्प

विशेष प्रतिनिधि

प्रदेश सरकार ने राजकीय कामकाज को सहज व सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं की ऐसी व्यवस्था स्थापित की है जिससे न केवल पारदर्शिता आई है, लोगों की परेशानियां भी कम हुई हैं। अब लोगों को अपने कार्यों के लिए चंडीगढ़ या जिला स्तर के मुख्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने गांव में सीएससी या घर पर कंप्यूटर के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस व्यवस्था को और सरल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य चल रहा है। आगामी कड़ी में प्रदेश में लोगों को ई-सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। आज जनहित की अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ जनता को घर बैठे मिल रहा है, जिस कारण पिछले सात साल में प्रदेश में हुए विकास से जनता को सुशासन स्पष्ट दिखाई देने लगा है, प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा लौट आया है।

प्रदेश में गरीब से गरीब व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाते हुए डीबीटी योजना के तहत लाभपात्रों को सीधा लाभ देना शुरू किया है। ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी बनाई गई है। योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। सरकारी सेवाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध पहुंचाने के लिए इन सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया। अब निर्धारित समय पर सेवा का लाभ न देने पर विभाग व अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है।

सरकार ने डायल-112 योजना शुरू की, जिससे लोगों को केवल 15 मिनट में पुलिस मदद मिल रही है। अब सुनने व बोलने में दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए डायल-112 में विडियो कॉल के द्वारा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बैठेंगे और उनकी समस्या सुन पुलिस मदद पहुंचाएंगे।

जनवरी-2022 से पीडीएस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा और इस योजना के तहत जन्म या मृत्यु होने पर लाभपात्र का नाम स्वतः जुड़ भी जाएगा और हट भी जाएगा। इसी प्रकार, प्रदेश में सीएलयू को ऑनलाइन किया गया है। ई-भूमि व वेब हैलरिस पोर्टल का काम जारी है। ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पहले ही बनाई जा चुकी है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल किया लांच

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गुरुग्राम में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाने की घोषणा के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल लांच किया व व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन पत्रिका तथा वर्ष-2022 के कलैंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले 78 अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सम्मानित किया।

अपने आप शुरू हो जाएगी पेंशन

सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज साबित होगा, जिससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को स्वतः मिलना संभव होगा, यानी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभपात्र की पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। प्रदेश के गांवों में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी के कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13 लाख 47 हजार 609 लोगों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं।

डा. कमल गुप्ता व देवेंद्र बबली मंत्रिमंडल में शामिल

हिसार से भाजपा के विधायक डा. कमल गुप्ता व टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली हरियाणा मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के रूप में शामिल हो गए। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को राज्यपाल भवन में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व अन्य गणमान्य मंत्रिमंडल सदस्य एवं विधायक उपस्थित रहे।

डा. कमल गुप्ता ने संस्कृत में मंत्री पद की शपथ ली जबकि देवेंद्र बबली ने हिंदी में बतौर केबिनेट मंत्री शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार काफी दिनों से लंबित चला आ रहा था जो आज पूरा हो गया। उन्होंने नए मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि वे पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करें। दुष्यंत चौटाला ने भी दोनों नए मंत्रियों को बधाई दी।

रचनात्मक रहा शीतकालीन सत्र

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र रचनात्मक रहा। चार दिन चले सत्र में राजकीय कामकाज की बेहतरी के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ अहम विषयों पर परिचर्चा हुई जिसके चलते यथा संशोधन आठ विधेयकों को पारित कर दिया गया।

माननीय सदस्यों की ओर से सदन में कुछ प्रस्तावित नीतियों को लेकर सवाल अवश्य उठाए गए लेकिन मुख्यमंत्री मनोहरलाल की नीयत को लेकर किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया गया। विपक्ष के जो सदस्य सरकार पर टिका-टिप्पणी करने से नहीं चूकते थे उन्होंने भी सीएम के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। काबिलेजिक्र है कि गत वर्ष कोविड काल और किसान आंदोलन के दौरान 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' नीति की कई बार परीक्षा हुई जिसमें राज्य सरकार सबका साथ लेकर सबका विकास कराती हुई नज़र आई।

विधानसभा के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि जब सभी विधायकों को बोलने का अवसर मिला। उक्त सत्र में 63 विधायकों ने सदन की प्रकिया में भाग लिया। मंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संख्या करीब 14 है। बाकी संख्या 76 रह जाती है। तीन विधायक अनुपस्थित रहे। चार ने बोलने की इच्छा जाहिर नहीं की। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि छह सदस्य ध्यानकर्षण प्रस्ताव के दौरान बोल चुके थे, इसलिए शून्यकाल में बोलने का प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। सत्र में कुलदीप बिश्नोई व गोपाल कांडा एक-एक दिन और प्रमोद विज दो दिन नहीं आए जबकि दूड़ाराम पारिवारिक कारणों से सदन में उपस्थित नहीं हो सके। सत्र चलने का समय सामान्यत चार घंटे होता है लेकिन अंतिम दिन सदन सात घंटे चला। सदन कुल 19 घंटे 53 मिनट चला।

हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप-सचिव के मामले को लेकर सदन में विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष की इस आशंका का निवारण करने के लिए जांच एजेंसी हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो की कार्य प्रगति के बारे में सदन को अवगत करवाया। विपक्ष ने सत्र आरंभ होने से पहले मीडिया में कहा था कि सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए यह पद सृजित किया। सीएम ने बताया कि यह कोई पहला मौका नहीं जब आयोग ने किसी आईएएस अधिकारी के सचिव रहते हुए उप-सचिव को कोई कार्यभार दिया हो। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 21.2.2014 को हरियाणा लोक सेवा आयोग में उप-सचिव का पद सृजित किया था मुख्यमंत्री ने एक नई शुरूआत करते हुए घोषणा की कि सत्र के अंतिम दिन शून्यकाल के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर एक महीने के अंदर सम्बंधित विधायकों को भिजवा दिए जाएंगे, जिसकी सभी विधायकों ने सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को पांच वर्ष में पांच करोड़ रुपए उनके अपने हलके में विकास करवाने के लिए दिए जाते हैं और जिन विधायकों की शेष राशि लंबित है, उन्हें यह 31 मार्च, 2022 तक पहुंचा दी जाएगी।

-संवाद ब्यूरो

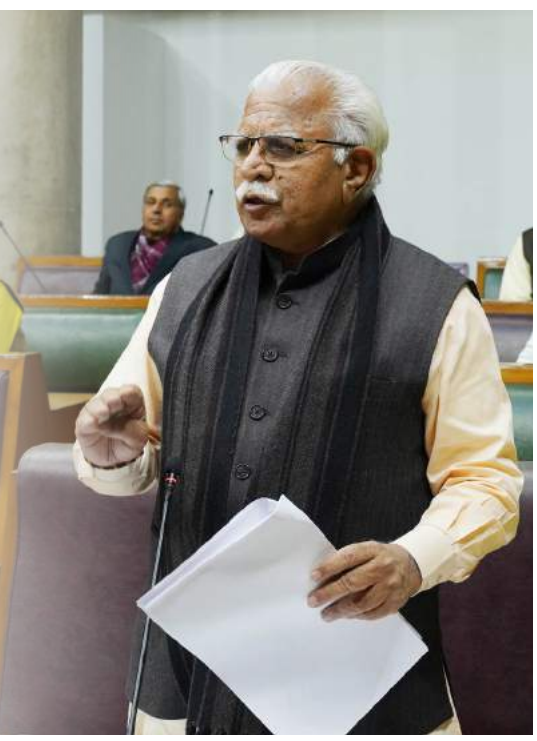

संपादकीय

अपनत्व करें बहाल

यह तय नहीं है कि नए वर्ष में कुछ ज़्यादा बदलाव आएंगे। मगर यह तय है तारीख भी बदलेगी, हम शुभकामनाओं का आदान-प्रदान भी करेंगे, प्रार्थनाएं भी करेंगे, संभव नेक काम भी करेंगे।

बीते दो वर्ष कुछ सुखद नहीं बीते। महामारी ने हमसे कुछ हमारे अपने भी छीने। जाने वालों में कुछ साहित्यकार भी थे, मनीषी भी थे। हम उन्हें समुचित मर्यादाओं और उनके महत्त्वपूर्ण अवदान के अनुरूप श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं कर पाए।

जीवन शैली में बदलाव आ गए। चर्चाएं, संगोष्ठियां, कविताएं, पठन-पाठन बहुत 'ऑनलाइन' हो गया। 'वर्क फ्रॉम होम' , ऑनलाइन कक्षाएं, 'सरीखी कुछ नई बातें, हमारे दैनिक जीवन का एक अंग बन गई। मगर ज़िंदगी का यह भी एक मोड़ था और अब प्रयास करना होगा कि पिछले अनुभव से बहुत कुछ सीखें, नया रास्ता चुनें, बेहतर रास्ता अपनाएं।'

'ऑनलाइन' के साथ-साथ सामान्य ज़िंदगी भी फिर से बहाल करें। नवसृजन, कंप्यूटर से हो या कलम से, थमना नहीं चाहिए। कभी अपनों के गले मिल कर देंखे, सुखद अनुभूतियां, सुखद संवेदनाएं, कुनमुनाएंगी। कुछ नया सोचें, कुछ नया लिखें, कुछ नया जिएं और सृजन की डगर पर कुछ नई उपलब्धियां दर्ज़ करें।

साथ ही एक कविता
ख़ामोशी की 'सिमसिम' खोलें
नया बरस है अब कुछ बोलें
मन का बोझीलापन धो लें
चलो नईं वेबसाइट खोलें।
सूरज खुद चल कर आया है,
चलो उठो, कुछ रोशन हो लें।
धूप, कुहासों को छेड़े है
हम भी मन की खिड़की खोलें
ख़ामोशी की सिमसिम खोलें
नया बरस है कुछ तो बोलें।

इसी संदर्भ में उर्दू के एक शिखर कवि की एक पुरानी नज़्म की कुछ पंक्तियां अनायास ही स्मरण हो आती है-

ऐ नये साल बता, तुझ में नयापन क्या है
रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही
आज हमको नज़र आती है, बात वही
किसे मालूम नहीं बारह महीने तेरे
जनवरी, फरवरी और मार्च में पड़ेगी सर्दी
और अप्रैल, मई, जून में होवेगी गर्मी
तू नया है तो दिखा सुबह नयी, शाम नई
वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई

डॉ. चंद्र त्रिखा

सात जनवरी से शुरू होगा अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण

गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में नई स्कीमें लेकर आएगी। इसके साथ-साथ पुरानी स्कीमों का भी रिव्यू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आगामी 7 जनवरी, 2022 से प्रदेशभर में अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। पहले चरण में 156 मेले आयोजित किए गए थे। इसमें डेढ़ लाख परिवारों में से 90 हजार ने हिस्सा लिया। इसमें आए बहुत से लोगों का ऋण भी मंजूर हो गया है। इन मेलों का मकसद गरीब परिवारों का रोजगार की तरफ रूझान बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र की तारीफ न केवल प्रदेश में हो रही है बल्कि देशभर में इसकी चर्चा की जा रही है। दूसरे प्रदेशों से लोग इस पैटर्न का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। सभी एडीसी को संवेदनशीलता के साथ इस काम को पूरा करना चाहिए। सभी का लक्ष्य गरीब और जरूरतमंद परिवार को आगे बढ़ाना है। इससे जुड़े अलग-अलग आइडिया पर काम करना चाहिए ताकि समयबद्ध तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। हमें पूरे जिले को आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को नौकरी की तरफ नहीं बल्कि रोजगार की तरफ लेकर जाना है ताकि वे नौकरी लेने वालों की बजाए, नौकरी देने वालों की कतार में हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया है। चौथे चरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सी योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से मिलने लगेगा। इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 55 साल से ऊपर है और अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी किसी स्कीम में विशेष प्रावधान किया जाएगा।

हायर एजुकेशन में जोड़े जाएं सामाजिक कार्यों के नंबर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विद्यार्थियों में सामाजिक सेवा व पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक विषयों पर भावना जागृत करने के लिए हायर एजुकेशन विभाग को कदम बढ़ाना चाहिए। भविष्य में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि कॉलेज व विश्वविद्यालयों में स्वच्छता, पेड़ लगाना, सफाई अभियान व सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों के नंबर दिए जाएं। इससे विद्यार्थियों में सामाजिक विषयों पर जागरूकता पैदा होगी।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा के कैंप लगाए जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र की तरह देशभर में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा स्कीम की भी तारीफ हो रही है। यह किसानों के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत साल में दो बार किसानों को अपनी फसल का ब्यौरा देना होता है। इससे 100 प्रतिशत भूमि की मैपिंग का कार्य भी हो जाएगा। जिला उपायुक्तों को ग्रामीण स्तर पर कैंपों का आयोजन कर, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस संदर्भ में जागरूक करना चाहिए। इसके साथ-साथ जिन किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है उनके नाम का चार्ट गांवों में लगाना चाहिए।

आशा वर्कर को मिलेगा 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की आशा वर्कर को 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत लाभ देने का निर्णय लिया है। विभागीय अधिकारियों को इस विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आशा वर्कर कम से कम दस वर्ष तक कार्य करने के उपरांत स्वैच्छिक तौर पर अपना कार्य छोड़ती हैं या सरकार के नियमानुसार 60 वर्ष की आयु के बाद कार्य से रिटायरमेंट दी जाती है तो उन्हें 20 हजार रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 108 आशा वर्कर 20 हजार रुपए की राशि के लिए योग्य हैं, जिनमें से 89 को 60 वर्ष की आयु के बाद कार्यमुक्त किया गया है तथा 19 आशा वर्करों ने अपना कार्य दस वर्ष के उपरांत छोड़ा है। उन्होंने बताया कि 71 आशा वर्करों को 20 हजार रुपए की राशि दी गई, 23 आशा वर्करों की राशि प्रक्रिया में है जबकि 24 को जिलावार जांच कर जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी।

उन्होंने आशा वर्करों की एक मांग पर कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा के अनुसार 20,012 आशा वर्करों की सूची उनके परिवार पहचान पत्र के साथ नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सत्यापन के लिए दी गई है। जैसे ही सभी आशा वर्करों के डाटा को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) द्वारा तैयार किए जा रहे यूटिलिटी माड्यूल में सत्यापित कर दिया जाएगा उसके उपरांत यह राशि आशा वर्करों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

नाबार्ड की परियोजनाएं तय समय में पूरी करें अधिकारी

वैश्विक महामारी के बावजूद भी हरियाणा राज्य में विकास की गति में कमी नहीं आई और हरियाणा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 44 प्रतिशत अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में देश में अग्रणी राज्यों में रहा। राज्य ने वर्ष 2019-20 में 715 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 1030 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की, जो प्रदेश में हो रही उन्नति को दर्शाता है।

मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 -22 के दौरान नाबार्ड द्वारा परियोजनाओं के लिए 1800 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1242 करोड़ रुपए अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार, 1400 करोड़ रुपए के संवितरण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 536 करोड़ रुपये से अधिक की अदायगी नाबार्ड द्वारा की जा चुकी है।

मुख्य सचिव ने वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड की परियोजनाओं के लिए 1100 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 1129.61 करोड़ रुपये (102 प्रतिशत) की परियोजनाएं अनुमोदित करने के लिए प्रशासनिक सचिवों और नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नाबार्ड के तहत चलाए जा रहे सभी प्रोजेक्ट को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें और इसके लिए प्रशासनिक सचिव स्वयं नियमित रूप से समीक्षा बैठक करें।

वित्त एवं आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन प्रसाद ने बैठक में सूक्ष्म सिंचाई, भंडारण, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी प्रसंस्करण और मत्स्य के बुनियादी ढांचा फंड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवलेपमैंट फंड के तहत ब्याज की दर 2.75 प्रतिशत है इसलिए अधिक से अधिक योजनाओं को नाबार्ड के तहत शुरू किया जाए।

बताया गया कि सोनीपत के बड़ी में बन रहा मेगा फूड पार्क का कार्य 31 मार्च 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। इस पर लगभग 169 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार, गन्नौर, सोनीपत की स्थापना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मंडी को 545 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है, जिसके लिए नाबार्ड 1600 करोड़ की सहायता प्रदान कर रहा है।

सूक्ष्म सिंचाई फंड के तहत नाबार्ड ने 790 करोड़ रुपये के चार प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। जिनमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और मिकाडा की परियोजनाएं शामिल हैं।

-संवाद ब्यूरो

हरियाणा पुलिस ने यातायात सुरक्षा से संबंधित त्वरित और मज़बूत आपात सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर-1073 को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली हेल्पलाइन-112 के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।

अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इस राशि से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ठीक साथ नया टर्मिनल बनाया जाएगा, जहां से विमान के लिए यात्रियों को टैक्सी-वे पर ले जाया जाएगा।

आयुष, लौटता भरोसा-बढ़ते कदम

मनोज प्रभाकर

भारत में सदियों से आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा प्रणालियों की स्वीकार्यता रही है। राजकीय प्रयासों के चलते हरियाणा में आयुष चिकित्सा पद्धति अपने मूल भरोसे की ओर लौट रही है। आयुष विभाग इन प्रयासों का निरंतर निर्वहन कर रहा है।

प्रदेश में इस समय राजकीय व निजी 14 आयुर्वेद व एक होम्योपैथी कालेज हैं, अंबाला में भी राज्य सरकार की ओर से एक होम्योपैथी कालेज शुरू किया जा रहा है। भिवानी, पंचकुला, पलवल, चरखीदादरी, कुरुक्षेत्र व नारनौल में आयुर्वेद अस्पताल हैं। इनके अलावा प्रदेश में 515 आयुर्वेद डिस्पेंसरी, 19 यूनानी डिस्पेंसरी व 26 होम्योपैथी डिस्पेंसरी हैं।

हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 407 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर तथा 138 सब-केंद्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव सैद्धांतिक मंजूरी पा चुका है। हरियाणा राज्य आयुष सोसायटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में निर्णय हो चुका है कि इन वैलनेस सेंटरों तथा सब-केंद्रों को स्थापित करने पर लगभग 64.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गत वर्ष तक 345 सेंटर तैयार हो चुके हैं।

पीएचसी में खुलेंगी आयुष विंग

राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एलोपैथिक) स्तर पर आयुष सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से 419 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट, सेवादार और अंशकालिक सफाई कर्मचारियों के पद सृजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इन पदों के सृजन के साथ-साथ आबंटित की जा सकने वाली स्कीम के क्रियान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 36 करोड़ रुपए के बजट के आयुष विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

पंचकर्मा सेंटर

स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शहरों में पंचकर्मा सेंटर बनाने हेतु उचित कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को शीघ्र योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचकर्मा सेंटर की बहुत मांग है। लोगों को लम्बे समय तक अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए सभी बड़े शहरों में इन केन्द्रों को प्राथमिकता आधार पर स्थापित करना होगा। बहरहाल कुल 21 सेंटर चल रहे हैं।

गांवों में योगशालाएं

प्रदेश की 'व्यायाम एवं योगशालाओं' के सफल संचालन हेतु एक हजार आयुष सहायक तथा 22 आयुष कोचों की भर्ती जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुबंध आधार पर की जा रही है। आयुष सहायकों को 11 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा, जोकि 18 से 35 वर्ष तक आयु वर्ग के होंगे। 22 आयुष कोचों की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित तौर पर की जाएगी।

आयुष पीजी कोर्स

श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र में 5 विषयों की 24 सीटों हेतु स्नातकोतर पाठ्य' म शुरू हुए हैं। इससे प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सों को उनके गृह प्रदेश में ही स्नातकोतर करने का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य में स्नातकोतर आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी भी दूर होगी।

नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ आयुर्वेद

माता मनसा देवी कॉम्पलेक्स में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ आयुर्वेदा का निर्माण होने जा रहा है। आयुर्वेद संस्थान के बनने से ट्राईसिटी के साथ-साथ हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के लगभग दो करोड़ लोगों को चिकित्सा सेवा का सीधा लाभ मिलेगा तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें। परियोजना पर लगभग 270.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 250 बेड के आईपीडी अस्पताल के साथ आयुर्वेद उपचार, शिक्षा और अनुसंधान के लिए युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।

जैविक विविधता का केंद्र मोरनी हिल्स

मोरनी व कलेसर में प्राकृतिक वन बहुतायत हैं। मोरनी क्षेत्र को औषधीय पौधों की जैविक विविधता का एक हॉट स्पाट केन्द्र माना गया है। विश्व औषधीय वन परियोजना के मुताबिक पतंजलि योगपीठ के 30 वैज्ञानिकों ने निरंतर मोरनी क्षेत्र में तीन बार सर्वे किया है और 983 जड़ी-बूटियों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान की है, जिनमें से 300 नई प्रजातियां हैं और 53 प्रजातियों की पहली बार पहचान की गई है। मोरनी के 715 हैक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योगपीठ द्वारा क्षेत्र में कुल 125 औषधीय वाटिकाएं विकसित की गई हैं।

सशक्त होती ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहे हैं। ढांचागत विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों के कार्य बोझ को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की सेवाओं को मजबूत करना बेहद जरुरी है। इसके लिए राज्य सरकार ने उप स्वास्थ्य केद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की ओर ध्यान दिया गया है। बहुत से केंद्रों को हैल्थ एंड वैलनेस सैंटर का रूप दिया गया है। इनमें दवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित करने का प्रयास है ताकि गांव के सामान्य मरीजों को शहर की ओर न भागना पड़े। बहुत से केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। जो केंद्र बचे हैं उन्हें भी जल्द विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार की योजना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुर्वेद चिकित्सा स्टाफ तैनात करने की भी है।

हरियाणा को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए 301.38 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ है।

उक्त बजट में से नैदानिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 27.87 करोड़ रुपए व उप-केंद्रों के लिए 24.16 करोड़ रुपए तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 6.98 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

इसके अलावा, राज्य में अर्बन हैल्थ एंड वैलनेस सैंटर की स्थापना के लिए 138 करोड़ रुपए,ब्लॉक स्तरीय पब्लिक हैल्थ यूनिट्स की स्थापना के लिए 28.34 करोड़ रुपए तथा प्रदेश में उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन-निर्माण के लिए 29.42 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केंद्रों को हैल्थ एंड वैलनेस सैंटर में बदलने के लिए 46.61 करोड़ रुपए का बजट मिला है।

वर्तमान में निजी व सरकारी क्षेत्र दोनों को मिला कर प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या करीब 14 हजार है जबकि यूएनओ के मानदंडों के अनुसार 1000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हरियाणा की जनसंख्या 2021 में 2.70 करोड़ मान कर चलते हैं तो 27 हजार डॉक्टरों की आवश्यकता है। इस मांग को पूरा करने के लिए राज्य की मनोहर सरकार ने हर वर्ष 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य के मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षा की सीटें बढ़ाई गई हैं। यहां से तैयार होने वाले डाक्टरों के लिए प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं अनिवार्य की जा रही हैं।

एक नज़र

आयुष विभाग के महानिदेशक डा. साकेत कुमार ने बताया कि झज्जर के देवरखाना में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस संस्था के प्रथम व द्वितीय तथा तृतीय फेस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ओपीडी की प्रि या शुरू हो चुकी है।

» राष्ट्रीय युनानी अनुसंधान संस्थान, फरीदाबाद को स्थापित करने हेतू राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत भारत सरकार को 68 कनाल 17 मरले गांव खेड़ी गुजरा फरीदाबाद की भूमि स्थानांतरित की जा चुकी है।

» अम्बाला के गांव चान्दपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कालेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा इस उदेश्य हेतू 61 कनाल 13 मरले जमीन के लिए राशि 3.39 करोड़ रुपए का भुगतान नगर निगम अम्बाला को किया जा चुका है।

» जिला नूह के गांव अकेड़ा में 45.43 करोड़ रुपये की लागत से राज्य का पहला राजकीय यूनानी कालेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा हैं। निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

» हिसार के गांव मय्यड़ में लगभग 15 एकड़ जमीन पर 50 बिस्तरों का आयुर्वेद अस्पताल खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जा चुकी है। अस्पताल का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

» आयुष हैल्थ एण्ड वेलनैस सैन्टर योजना के तहत कुल 407 आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हैल्थ वेलनैस सैन्टर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है जिनमें से 10 आयुष औषधालयों को आयुष हैल्थ वेलनैस सैन्टर के रूप में अपग्रेड करके उद्घाटन किया जा चुका है तथा 337 आयुष हैल्थ वेलनैस सैन्टर के अपग्रेड का कार्य किया जा चुका है तथा 13 आयुष औषधालयों को आयुष हैल्थ वेलनैस सैन्टर के रूप में अपग्रेड करने का कार्य चल रहा है।

» नारनौल के पट्टीकरा में बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कालेज/अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अस्पताल में ओपीडी/आईपीडी की सुविधा शुरू की जा चुकी है।

» कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आयुष विभाग द्वारा पुलिस विभाग, नगरपालिकाओं, पचांयती राज, उपायुक्त कार्यालय, वृद्ध आश्रम, वरिष्ठ नागरिको व अन्य कन्टेन्मैन्ट जोन मे कुल 26.73 लाख व्यक्ति यों को दवाईयां वितरित की गई है।

» नए आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालय - गावं निमली (चरखी दादरी), गांव धूरखडा व अधोई (अम्बाला), आह्लदपुर, गढी ब्राहम्ण, नाहरी व जाट धर्मशाला (सोनीपत), कालवन (जीन्द), उगालन, महजत, मदनहेडी, लोहारी राघो, खानपुर व बडछप्पर (जिला हिसार) कलेसर व जिला कारागार (यमुनानगर), पाढा (करनाल), नांगल नुनिया (नारनौल), कुराड (पानीपत), कसरैंटी, मोखरा रोज (रोहतक) व सिल्खों (मेवात) मे राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों तथा चनारथल व बारवा (कुरूक्षेत्र), गारनपुरा कलां (भिवानी) मे राजकीय होम्योपैथिक औषधालय व डबवाली (सिरसा) मे आयुष विंग की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऊन (चरखी दादरी) व चैनत (जिला हिसार) मे सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकाल मे स्वीकृति प्रदान की गई है।

देश में 90 और प्रदेश के झज्जर जिला में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आधुनिक तकनीक पर आधारित कैंसर मेडिकल अस्पताल बनाया गया है।

कुरूक्षेत्र जेल में पहला पेट्रोल और सीएनजी पंप लगाया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) की तरफ़ से लगाए जाने वाले इस पेट्रोल और सीएनजी पंप पर करीब तीन करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे।

शीतकालीन सत्र

विशेष प्रतिनिधि

हरियाणा विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आठ विधेयक पास हुए। सत्र के पहले दिन हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया गया। राज्य के कई जिलों में भूमिगत जल की भयावह स्थिति और तालाबों की अत्यधिक ख़राब स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण (संशोधित) विधेयक, 2021 पास किया गया। अंतिम दिन छह विधेयक पारित किए गए, जिनमें हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2021; हरियाणा अनुसूचित सडक़ तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021; हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021; पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021; हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2021 और हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2021 शामिल हैं।

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है। राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतू शैक्षणिक संस्थाओं के सृजन और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर वर्ष 2021 तक संस्थाओं का संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। पानीपत में गीता विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव किया गया है।

हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण

राज्य के कई जिलों में भूमिगत जल की भयावह स्थिति और तालाबों की अत्यधिक ख़राब स्थिति से निपटने के लिए राज्यभर में कई तालाबों की योजना और जीर्णोद्धार/विकास कार्य प्रगति पर है। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण में प्राधिकरण चलाने के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार और सदस्य सचिव नियुक्त है। इनमें से कुछ अधिकारी शीघ्र ही 65 वर्ष के हो जाएंगे। इसके अनुसार ''असाधारण मामलों में सरकार इनमें से किसी भी अधिकारी को 68 वर्ष की आयु तक कारण दर्ज करके पद पर बने रहने की अनुमति दे सकती है''। इन्ही तथ्यों के मद्देनजर हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण (संशोधित) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।

नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन

हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 27 में प्रावधान रहा कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार द्वारा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम, 1914 की धारा 27, 29, 30 और 62 में उपबंधित पच्चीस वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा

कोविड को लेकर एक जनवरी से नए नियम

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आगामी एक जनवरी, 2022 से हरियाणा राज्य में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे कि रेस्टोरेंट्स, मॉल, बैंक, कार्यालय इत्यादि में कोरोना की दूसरी डोज ना लगवाने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हम हरियाणा को देश में ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश होगा जो देशभर में ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा।

कोरियावास, भिवानी और जींद के मेडिकल कॉलेज का वर्क अलाट कर दिया गया है और यमुनानगर, सिरसा और गुरुग्राम के मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रक्रियाधीन है। विज ने कहा कि अभी तक बूस्टर डोज के संबंध में केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

आशंकित लहर से निपटने के इंतजाम

कोविड से निपटने के लिए राज्य के तैयारी के संबंध में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार (सीएवी) को बढावा देने के लिए आक्रामक प्रचार (आई.ई.सी.) किया जा रहा है। राज्य में कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत कुल 1097 है जिनमें 69 डेडीकेटिक कोविड अस्पताल, 588 डेडीकेटिड कोविड स्वास्थ्य केन्द्र, 440 डेडीकेटिड कोविड केयर सेंटर, 59932 आईसोलेसन बिस्तर, 5367 बच्चों के लिए आईसोलेशन बिस्तर, 16757 आक्सीजन उपलब्धता बिस्तर, 3865 बच्चों के लिए आक्सीजन उपलब्धता बिस्तर, 5974 आईसीयू बिस्तर, 2140 बच्चों के लिए आईसीयू बिस्तर, 2385 वेटिलेटर, 719 बच्चों के लिए वेंटिलेटर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 10000 से अधिक आक्सी उपलब्धता बिस्तर व 650 आईसीयू बिस्तर हैं। इसी प्रकार, पीएसए संयंत्र 75 स्थापित किए गए हैं (40 पीएम केयर से और 35 सीएसआर के तहट) जिनमें से 72 क्रियाशील है। इसके अलावा, निजी बहुसुविधा अस्पतालों में भी 54 पीएसए संयंत्र स्थापित किये गये है।

हरियाणा सरकार द्वारा भविष्य में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पेंशन बनाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्वास्थ्य ढांचे का उन्नयन के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए 537.16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

आठ विधेयक पारित

को घटाकर इक्कीस वर्ष करने के लिए हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।

सडक़ तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन

हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण), विधेयक, 2021 पारित किया गया है। यह मुख्य रूप से हरियाणा अनुसूचित सड़कों और नियंत्रित क्षेत्रों के अनियंत्रित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 की धारा 12 ग (1) के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट वैधानिक प्रावधान करने और इस विषय पर परस्पर विरोधी न्यायिक घोषणायें, यदि कोई हों, के बावजूद सरकार व विभाग द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियों को मान्य करने के लिए प्रस्तावित किया गया।

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 5(ण) में आने वाला शब्द और चिह्न 'मण्डल आयुक्त पंचकूला' अस्पष्टता पैदा करता है जिसे स्पष्ट प्रावधान द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता थी इसलिए पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।

हरियाणा कृषि उपज मण्डी

हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 इसकी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कृषि उपज तथा ऐसी कृषि उपज के प्रसंस्कृत उत्पाद के विक्रय, क्रय, प्रसंस्करण आदि को विनियमित करता है। तथापि कतिपय प्रसंस्करण में ऐसे प्रसंस्कृत उत्पाद कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं जोकि मुख्य रूप से व्यापारियों से खरीदे जाते हैं किसानों से नहीं खरीदे जाते। इसलिए, सरकार के 'कारोबार की सहूलियत' के मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि यथा मूल्य आधार के बदले में एकमुश्त आधार पर ऐसी प्रसंस्करण इकाइयों पर मण्डी फीस लगाने के लिए समर्थ उपबंध किए जाने चाहिए।

हरियाणा विनियोग

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में मार्च, 2022 के इकत्तीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से 73,12,66,09,000 रुपए की अपेक्षित राशि के भुगतान और विनियोग हेतु उपबंध करने के लिए पारित किया गया है।

नए सिरे से शुरू होगी जनगणना

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एक जनवरी 2022 से नए सिरे से राज्य में भी जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा जिसमें 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में महाग्राम योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, 8 से 10 हजार तक की आबादी वाले गांवों में दूसरी एफएसटीपी की सुविधा को अपग्रेड किया जाएगा, 5 से 8 हजार तक की आबादी वाले गांवों को भी पोंड अथोरिटी एक नई योजना के साथ टेकअप करेगी।

विधायक आदर्श ग्राम योजना

हरियाणा में शहरी विधानसभा क्षेत्र का विधायक 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' के तहत विकास के लिए अपने नजदीकी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव का चयन कर सकता है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 26 दिसंबर 2018 को निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रति वर्ष गांव की जनसंख्या के आधार पर 2 करोड़ रूपए तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। एक विधायक 5,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए 50 लाख रूपए, 5 से 10 हजार आबादी तक वाले गांव के लिए एक करोड़ रूपए तथा 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांव के लिए 2 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती जल्द

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में पहली बार डॉक्टरों का स्पेशलिस्ट केडर तैयार किया जा रहा है और इसकी प्रारूप नीति तैयार है जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि अब डॉक्टरों की भर्ती का जो भी विज्ञापन होगा वह स्पेशलिस्ट के अनुसार से ही होगा।

विभागीय चयन समिति के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों के 980 पदों को नियमित आधार पर भरा जा रहा है और उक्त पद का विज्ञापन शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। विभिन्न पैरामेडिकल पदों के लिए मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है जो भर्ती की सक्रिय प्रक्रिया के तहत है।

किसान आंदोलन के केस वापसी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 276 केस दर्ज हुए थे। इनमें से 4 केस अति गंभीर प्रकृति के हैं। 272 केस में से 178 केस में चार्जशीट तैयार की गई है। 158 केस अभी तक अनट्रेस हैं। 8 की कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और चार केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। 29 केस रद्द करने की प्रक्रिया जारी है।

नियुक्ति को लेकर कमेटी

हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अलग-अलग पदों पर नियुक्ति यों के संबंध में फैसला लेने को लेकर पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्यपाल (चांसलर) का प्रतिनिधि, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव तथा तीन यूनिवर्सिटी के वीसी शामिल होंगे। इसमें यूजीसी के निर्देशों की अनुपालना की जाएगी।

नंबरदारों को नहीं हटाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नंबरदारों को नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा नम्बरदारों का मानदेय 1500 रुपए से 3000 रुपए करने तथा स्मार्ट फोन के लिए 7000 रुपए देने के निर्णय की जानकारी सदन को दी गई। इसके अलावा उन्हें 'आयुष्मान भारत' का लाभ देने का निर्णय भी लिया है। सरकार ने आगे नए नंबरदार की नियुक्त पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है।

महंगाई भत्ता बढ़ाया

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों एवं परिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की दर को एक जुलाई, 2021 से मूल वेतन एवं पेशन का 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नए कर्मचारियों के लिए क्रियान्वित एनपीएस योजना का शेयर केंद्र सरकार की तर्ज़ पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है, जो एक जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा।

विश्वविद्यालयों की स्वायतता पर चर्चा

प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयो में नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार नया विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक को लेकर शीतकालीन सत्र में सरकार व विपक्ष के बची काफी चर्चा हुई। विपक्ष ने इसे विश्वविद्यालयों की स्वायतता के लिए सही नहीं बताया तो सरकार ने कहा कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा करना समय की मांग है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संसोधित विधेयक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कहा कि विश्वविद्यालयों में पूर्व की भांति उपकुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से ही होगी, जो सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति पहले भी सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा ग्रुप-बी, नॉन टीचिंग, ग्रुप सी और डी व एसिसटेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 22 राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। जाट-पाली, महेंद्रगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। इसके अलावा, 23 निजी विश्वविद्यालय, 01 प्रतिष्ठित संस्थान और 9 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

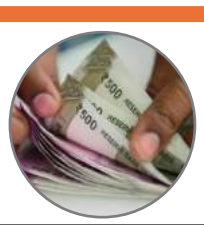

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए डी.ए. की दरों को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। इससे प्रदेश के कोष पर 672 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त भार पड़ेगा।

हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार की तर्ज़ पर नियोक्ता अंशदान को एक जनवरी, 2022 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने जा रही है।

प्रदेश में खाद व उर्वरक की कोई कमी नहीं

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश में खाद व उर्वरक की कोई कमी नहीं है। गेहूं और सरसों की बिजाई के लिए प्रदेश सरकार ने पर्याप्त मात्रा में खाद को उपलब्ध करवाया है। राज्य में अभी तक 6 लाख 93 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 2 लाख 82 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 1 लाख टन से ज्यादा एसएसपी, 41 हजार से ज्यादा एनपीके की उपलब्धता है, जिसमें से 6 लाख 24 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 2 लाख 60 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 79 हजार मीट्रिक टन एसएसपी, 38 हजार 661 मीट्रिक टन एनपीके किसानों को उपलब्ध करवा दिया गया है।

कृषि मंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि हर जिले में बिजाई को ध्यान में रखते हुए खाद को उपलब्ध करवाया गया है। केंद्र सरकार के साथ खुद मुख्यमंत्री ने बातचीत कर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की है। प्रदेश सरकार ने कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की। 22 जिलों में 61 शिकायतें मिलीं, 157 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 88 के लाइसेंस निलबिंत किए गए और 20 पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ-साथ 1685 टीमों ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी की। हरियाणा राज्य में रबी फसलों मुख्यतः गेहूं तथा सरसों की बिजाई के दौरान डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की कोई गंभीर कमी नहीं देखी गई।

पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा खाद दिया

कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले रबी मौसम में 2.58 लाख मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी, जबकि वर्तमान मौसम के दौरान 15 दिसंबर, 2021 तक 2.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मात्रा किसानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है जोकि पिछले वर्ष की डीएपी खपत के लगभग बराबर है। इसके साथ-साथ फॉस्फेटिक उर्वरकों के अन्य स्त्रोतों जैसे एसएसपी तथा एनपीके को भी पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा (एसएसपी दो गुना से अधिक और एनपीके लगभग 5 गुना)में उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार 15 दिसम्बर,2021 तक फॉस्फेटिक उर्वरकों की कुल खपत 3.73 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक इनकी खपत 3.01 लाख मीट्रिक टन थी।

इसी प्रकार, पिछले वर्ष के दौरान यूरिया उर्वरक की बि'ी 5.88 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि वर्तमान रबी मौसम के दौरान यह 5.74 लाख मीट्रिक टन रही जो यह दर्शाती है कि इस वर्ष किसानों को यूरिया की लगभग समान आपूर्ति हुई है।

किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए 428 करोड़

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा कि हाल ही में भावांतर भरपाई योजना के तहत 2.38.245 लाख बाजरा उगाने वाले किसानों के खातों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग बिना किसी शिकायत के सफलतापूर्वक 428.07 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए है। पिछले तीन वर्षों में (2019 से वर्ष 2021-22 तक) कुल 43,307 करोड़ रबी सीजन के दौरान और 34,732 करोड़ रुपए खरीफ सीजन के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से किसानों की एमएसपी पर खरीद बारे पेमेन्ट की गई।

भूमि को लेकर मैपिंग का कार्य जारी

प्रदेश की सभी जोत भूमि को लेकर मैपिंग का कार्य करवाया जा रहा है, इसके माध्यम से सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किया जा रहा है। इस भूमि का पूरा रिकार्ड आ जाने के बाद किसानों की सुविधा क्षेत्र अनुसार मंडी, बिक्री केंद्र आदि और अन्य केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में किसानों की मदद के लिए हेल्प डेस्क खोले जाते है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की असुविधा व अन्य शिकायतों का निवारण आसानी से किया जाता है।

कृषि मंत्री ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न प्रकार के किसान अर्थात भूमि मालिक, बोने वाला किसान, ठेका किसान, साझा किसान, पट्टा किसान, भूमि मालिकों के संबंध में किसान और मिश्रित किसान अपना व्यक्ति गत विवरण, भूमि रिकॉर्ड, फसल, बैंक खाता आदि देकर एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है ।

पपीते की खेती ने किया मालामाल

रिटायर होने के बाद ज़िंदगी थम नहीं जाती, बल्कि हमें लगातार कुछ नये व अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। इस बात को अपने जीवन में अपनाते हुए झज्जर के पटौदा गांव के 61 वर्षीय किसान रमेश चंद्र ने पपीते की खेती में बेहतरीन कार्य किया। जैविक व जहरमुक्त सब्ज़ी व फल लोगों को उपलब्ध करवाकर वह अपने आपको खुशकिस्मत मानते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं।

रमेश चंद्र कहते हैं पपीता की खेती के लिए बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इस समय डेढ़ एकड़ ज़मीन पर 1,500 पेड़ लगे हुए हैं। इनमें से अधिकतर पौधे 20 किलो से 40 किलो फलों से लदे हुए हैं। पपीते गांवों के आस-पास के लोग खरीदकर ले जाते हैं। जैविक पपीते 40 से 50 रुपए किलो प्रति के हिसाब से बिकते हैं। शादी सीजन में लोग एक से डेढ़ क्विंटल पपीता खरीदकर ले जाते हैं और इस खेती से उन्हें अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है।

सोशल मीडिया से सीखी जैविक खेती

रमेश चंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया फेसबुक, यू-ट्यूब और व्हाट्सअप के माध्यम से जैविक खेती के गुर सीखे और उससे अपनी खेती में सुधार किया है। जैविक खेती के विशेषज्ञ सुभाष पालेकर, राजीव दीक्षित, कृष्ण चंद्रा को फोलो करते हैं और उनके बताएं हर पहलूओं को जैविक खेती में अपनाते हैं। उनके पपीते की ख़ासियत है कि इसमें मिठास अधिक और स्वाद भी अन्य पपीते की तुलना में अधिक रसीला है। यह जहररहित है और पेड़ पर स्वयं पकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती और अधिक दिन तक यह ख़राब नहीं होता। उन्होंने बताया कि पपीता के खेती के लिए हरियाणा का मौसम अनुकूल नहीं है और साथ ही किसानों को इस खेती के बारे में सही जानकारी नहीं है। इसके कारण पपीते की खेती विफल होने के कारण वह इस ओर हाथ नहीं बढ़ाते। रमेश चंद्र ने पपीता की खेती में नीला थोथा, फंगीसाइड, नीम व सरसों की खल, नीम का तेल व छाछ का प्रयोग करते हैं।

पपीते की एक नई किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित की गई है, जिसे रेड लेडी 786 नाम दिया है। यह एक संकर किस्म है। इस किस्म की खासियत यह है कि नर व मादा फूल ही पौधे पर होते हैं, लिहाजा हर पौधे से फल मिलने की गारंटी होती है।

पपीते की खेती के लिए जलवायु व भूमि

पपीते की अच्छी खेती गर्म नमी युक्त जलवायु में की जा सकती है। इसे अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होने पर उगाया जा सकता है, न्यूनतम पांच डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। लू तथा पाले से पपीते को बहुत नुकसान होता है। पपीता बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला पेड़ है। साधारण ज़मीन, थोड़ी गर्मी और अच्छी धूप मिले तो यह पेड़ अच्छा पनपता है, पर इसे अधिक पानी या ज़मीन में क्षार की ज़्यादा मात्रा रास नहीं आता है।

-संगीता शर्मा

गुणकारी है पपीता

पपीता के अनेक स्वास्थ्यवर्द्धक लाभ होते हैं। स्वाद और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के कारण पपीता एक लोकप्रिय फल है। पपीते की ख़ासियत है कि ये मौसमी फल न होकर सालभर मिलता है। लोग इसे नाश्ते और फ्रूट सलाद में पपीते का सेवन करते हैं। पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। पपीते में एंटी आक्सीडेंट पोषक तत्व कैरोटिन,पोटैशियम, मैग्नीशियम, रेशा और विटामिन ए, बी, सी सहित कई अन्य गुणकारी तत्व भी पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है जो त्वचा को नम रखने में सहायक होता है।

प्रदेश की सभी जोत भूमि की मैपिंग के माध्यम से किसानों का रजिस्ट्रेशन 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर किया जा रहा है। सुविधा क्षेत्र अनुसार मंडी, बिक्री केंद्र और अन्य केंद्र बनाए जाएंगे।

एक जनवरी 2022 से नए सिरे से राज्य में भी जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा जिसमें 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में महाग्राम योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे।

नौकरियों में प्रतिभाओं को मिल रहा सम्मान

विशेष प्रतिनिधि

हरियाणा प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मौका मिलता है तो अनेक मौकों पर युवाओं की ओर से प्रतिभा का इज़हार देखने को मिलता है। शिक्षा, खेल, कृषि व अन्य क्षेत्रों में युवक व युवतियां दुनियाभर में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र की नौकरियों की बात है तो पिछले करीब सात आठ साल से कुशल एवं योग्य युवाओं को इस क्षेत्र में भरपूर अवसर मिल रहा है। जो युवा और उनके परिजन पहले सिफारिश और पैसे के बंदोबस्त की बात करते थे वे अब परीक्षाओं में अव्वल आने के लिए पढ़ने और पढ़ाने की बात करने लगे हैं। यह नज़ारा प्रदेश के शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटरों व पुस्तकालयों में देखा जा सकता है। लड़के व लड़कियां पढ़ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय दे रहे हैं। कहना गलत न होगा पांच सात साल पहले तक युवाओं ने पढ़ना कम कर दिया था। जो मेहनती युवा थे वे व्यवस्था से निराश हो चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सफलता के लिए पलायन भी शुरू कर दिया था। अब व्यवस्था बदल चुकी है, व्यवस्था के साथ शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटरों का माहौल बदल चुका है। मनोहर सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए जो व्यवस्था स्थापित की गई है उससे राजनीतिक गलियारों का माहौल भी बदल गया है। जो युवा और परिजन नौकरियों के लिए राजनीति से संबंद्ध रखने वाले लोगों के चारों ओर चक्कर काटते थे वे अब काबिलियत पर ध्यान देने लगे हैं। सरकार में एक विधायक के प्रभाव और ताकत का यह पैमाना होता था कि वह अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिशत अभ्यार्थियों को नौकरी दिलवाता था।

वर्तमान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का फैसला किया। यह सुस्पष्ट संदेश है कि सरकारी नौकरी के लिए केवल और केवल योग्यता ही एक पैमाना रहेगा। इस व्यवस्था के चलते हरियाणा में एक कुल्फी बेचने वाले और एक पोस्टमैन के बेटे ने 2016 में हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वर्तमान सरकार 84 हजार से अधिक युवाओं को नियमित सरकारी नियुक्तियां दे चुकी है। 20 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है।

पिछली सरकार द्वारा चयनित 10 हजार युवाओं के भविष्य पर लटकी हुई तलवार को भी हटाया गया। उनकी नियुक्तियों पर विभिन्न न्यायिक मामलों के कारण रोक लगी हुई थी। नव चयनित युवाओं को इस बात का संतोष रहता है कि अंतिम साक्षात्कार के कुछ ही घंटों के अंतराल पर उनका परिणाम घोषित कर दिया जाता है। हरियाणा में यह बातें पहले कभी नहीं हुई थी। अब ये सामान्य बातें हैं और पूरी गंभीरता से खामोशी के साथ लागू हो रही हैं।

सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बड़े सीमित हैं। फिर भी विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर योग्यता एवं पारदर्शिता से भर्ती के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। योग्यता के आधार पर और पारदर्शी ढंग से युवाओं को नौकरियां देने का अपना वायदा पूरा किया जा रहा है। हाल ही में पुलिस में 1,100 महिला कांस्टेबल की भर्ती का परिणाम आया । इसमें ऐसी बेटियों का भी चयन हुआ, जिनके परिवार में कभी किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। पारदर्शिता का स्तर देखिए। इस भर्ती के परिणाम में केवल रोल नंबर नहीं प्रकाशित किये गये, बल्कि चयनित उम्मीदवारों के नाम, पता व मोबाइल नंबर तक सार्वजनिक किये गये।

एचसीएस में पदोन्नति

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है, जबकि पहले यह पदोन्नति केवल साक्षात्कार के आधार पर की जाती थी। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में से आईएएस की पदोन्नति के लिए भी लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। यही नहीं, चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है ।

के वल लिखित परीक्षा के आधार पर ही इन पदों पर नियुक्ति की जा रही हैं।

पुलिस भर्ती में पारदर्शिता

ग्रुप सी व डी पदों पर भर्तियों की लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक व अनुभव और सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित किये गये हैं। 'पुलिस भर्ती में पारदर्शिता' (टी.आर.पी.) पद्धति लागू की गई है।

खिलाड़ियों को उचित अवसर

खिलाड़ियों के लिए ग्रुप ए, बी, सी, डी श्रेणियों के पदों में उनकी खेल उपलब्धियों के अनुसार नौकरी प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई है ताकि उन्हें अपनी खेल उपलब्धि के अनुसार नौकरी मिले और किसी भी खिलाड़ी के साथ भेदभाव न हो।

पेपर लीक वालों को सजा

पेपर लीक या नकल के दोषी को दो साल तक भर्ती परीक्षा वंचित करने, दो से दस साल तक की सजा और 5 हजार से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके लिए 'हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2021' पारित करवाया गया है।

युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए 'एकल पंजीकरण' की सुविधा शुरू की। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए 'कॉमन पात्रता परीक्षा' का प्रावधान किया गया।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस दिशा में 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाए। इसके अलावा, सरकारी भर्तियों में भी उस परिवार के उम्मीदवार को 5 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं जिसका कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है।

कौशल रोजगार निगम का गठन

युवाओं के आर्थिक शोषण को खत्म करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। यह आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। सर्वविदित है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां सीमित हैं। फिर भी वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में 84 हजार से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरियां दीं।

उद्योगों के जरिए रोजगार

प्रदेश में 48 हजार नये उद्योग लगे हैं, जिनमें 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2005 में सत्ता की बागडोर सम्भालते ही सबसे पहला काम हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल को खत्म करके कर्मचारी विरोधी होने का प्रमाण दिया था।

कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया

कांग्रेस सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाली नीति भी कोर्ट ने रद्द कर दी थी और 4,645 कर्मचारियों को छह महीने में निकालने का आदेश दिया था। उन्हें समायोजित किया गया। इसी प्रकार 9,455 जेबीटी शिक्षकों और इनेलो सरकार में भर्ती किए गए 3,500 सिपाही जिन्हें कांग्रेस सरकार ने निकाल दिया था, उन्हें भी समायोजित किया।

गेस्ट टीचरों का समायोजन

गेस्ट टीचर के नाम पर हजारों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस सरकार की गलती को सुधारने का काम किया गया। इसके लिए गेस्ट टीचर्स के लिए सेवा सुरक्षा नियम बनाकर उनकी नौकरी बचाई।

कांग्रेस शासनकाल की 12 भर्तियों को कोर्ट रद्द कर चुका है। इनमें पिछली सरकार ने 17,208 युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया।

हरियाणा में पहली बार डॉक्टरों का स्पेशलिस्ट केडर तैयार किया जा रहा है और इसकी प्रारूप नीति तैयार है जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा।

प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में करीब 127 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

देसी खाणा, देसी बाणा, इसा म्हारा हरियाणा

'म्हारा देस हरियाणा जित दूध दही का खाणा' कहावत यूं ही लोकप्रिय नहीं है। खेलों की दुनिया में हरियाणा के युवाओं का डंका बज रहा है। इसके अलावा प्रदेश का हर दसवां युवा सेनाओं में तैनात है। कृषि क्षेत्र में अग्रणी है। इतना ही नहीं बौद्धिकता के मामले में भी अब यह सूबा किसी से पीछे नहीं रह गया है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। कहना गलत न होगा विश्व के अनेक देशों में हरियाणा वासियों की धूम है।

गाहे-बगाहे देश-विदेश में चर्चा होती हैं कि हरियाणा की माटी से इतनी प्रतिभाओं के निकलकर आने की वजह क्या हैं? वजह अनेक हैं लेकिन एक प्रमुख और बुनियादी वजह यहां के खानपान की संस्कृति है। प्रदेश की आबोहवा में बेशक आधुनिकता का रंग चढ़ा हो लेकिन जब खानपान का मौका होता है तो आधुनिकता को अहमियत नहीं दी जाती। यहां की रसोइयों में देसी खानपान का बोलबाला रहता है। ऋतु के अनुसार खानपान तैयार किया जाता है।

सर्दियों के मौसम में हमारी माताएं आज भी गोंद के लड्डू, बेसन के लड्डू, बेलगरी आदि क्षेत्रवार पकवान तैयार करती हैं ताकि सर्दी व रोगों से बचने के लिए शरीर को ताकत मिल सके। मौसम के अनुसार अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं जिनसे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। कहा भी जाता है कि देसी खाणा, देसी बाणा, इसा म्हारा देस हरियाणा। शारीरिक मेहनत यहां की संस्कृति में रची बसी है।

सर्दियों में खाने का जायका बदल जाता है। गाजर का हलवा, गोंद की बर्फी या सरसों का साग। इस मौसम में खाने की कई किस्में सेवन के लिए मिल जाती हैं। गोंद, बेसन, तिल, नारियल व ड्राई फ्रूट से बने लड्डू या बर्फी न केवल हमें सर्दी से बचाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अति उत्तम होते हैं।

गाजर का सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इनसे गाजरपाक या लड्डू आसानी से घर पर बनाए जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट पंजीरी रेसिपी एक ऐसी चीज है जिसे खाने का कोई तय वक्त या मौसम नहीं होता। इसे जब मर्जी बनाया जा सकता है। तिल अथवा मूंगफली के लड्डू भी बनाए जाते हैं।

सर्दी में खान-पान करें बेहतर

सर्दियों में एक तरफ जहां फल-सब्जियों की भरमार होती है, वहीं दूसरी ओर लड्डू, पिन्नी, गुड़-मूंगफली, गजक, रेवड़ी जैसे मिठाई के तौर पर खाए जाने वाले खाद्य-पदार्थों की ढेरों किस्में बाज़ार में मिलती हैं। ऐसे में पौष्टिकता से भरपूर इन चीजों को हम अपने आहार में शामिल करके शरीर को अधिक तंदुरूस्त बना सकते हैं। इस मौसम में फलों, सब्ज़ियों और ड्राई फ्रूट्स के सेवन से हमारे शरीर को भरपूर पोषण मिलता है। इसके चलते हम सर्दी, जुकाम, वायरल जैसी बिमारियों से आसानी से बच जाते हैं।

गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। पर इसे सर्दियों में खाने के और भी कई फ़ायदे हैं। सर्दियों में बादाम, किशमिश, अंजीर, मूंगफली, तिल, अलसी के साथ-साथ कई तरह के ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं। इन सभी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स को गर्म दूध, हलवे या मिठाई जैसी चीजों के साथ खा सकते हैं। सर्दियों में इलायची, लौंग, हल्दी और अदरक का इस्तेमाल आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है। सर्दियों में ये मसाले आपके शरीर को गरम रखने में मदद करते हैं। शहद के कई ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे आपके शरीर को चुस्ती और फुर्ती मिलती है। यह नेचुरल तौर पर मीठा है इसलिए इसे चीनी की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण फल

सेब, अनार, संतरा, अमरूद, किन्नू, कीवी जैसे खट्टे जूसी साइट्रस फल दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। ये सभी विटामिन सी, पेक्टिन फाइबर, लाइमोनीन, फाइटोकैमिकल्स से भरपूर ये फल जूस से भरपूर हैं। इनके नियमित सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जिससे वायरल संक्रमण से होने वाले जुकाम-खांसी, फ्लू, वायरल जैसे रोगों से बचाव होता है।

हरी सब्ज़ियों का सेवन करें

ठंड के दिनों में खाने पीने के लिए ढेर सारी सब्ज़ियां होती हैं, जिनमें सबसे ख़ास होती हैं हरी पत्तेदार सब्ज़ियां। इनमें कुछ साग तो साल भर मिल जाती हैं, लेकिन कुछ सिर्फ ठंड के मौसम में ही आती हैं।

मेथी, बथुआ, सरसों, पालक, धनिया आमतौर पर मिल जाते हैं। इनके खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है साथ में रक्त की कमी भी दूर होती है जिसकी वजह से खासकर महिलाओं में क्षीणता या बदन दर्द की शिकायत रहती है।

-संवाद ब्यूरो

सुण छबीले बोल रसीले

जाड्डे और ठाड्डे तै बचकै रहणा चाहिए

-रसीले, आज पैग लगाणे नै मन करै सै।

-क्यूं के आफत आगी?

- आफत आवै जिबै लगाया करैं।

- हां, जिसका माथा खराब होर्‌या हो, वो ये उल्टे - सीधे काम कर्‌या करै।

- माथा तो पड़ौस के सीएम का भी खराब होर्‌या सै, जो म्हारी सरकार पै चंडीगढ़ नै पंजाब ताहीं देणे के प्रयास का आरोप लावै।

- पर वो बोहत स्याणा सै। दारू कोन्या पीवै। झूठ साच बोलकै आपणी राजनीति चमका लेगा।

- मैं पील्यूंगा तो के बिजली पड़ज्यागी?

- रसीले, सरकार नशा विरोधी अभियान चलावै सै। तनै देख्या नहीं करनाल में सीएम ने खुद भी शपथ ली और बालकां ताहीं बी दिलवाई, अक जिंदगी में कभी नशा नहीं करैंगे। नशा करणिए माणस का कदे बस्या नहीं करता। वो चाहे कितणाए एंडी बणर्‌या हो, पर समाज में उसकी दो धेले की वैल्यू ना होती। कोई उसतैं सीरियसली बात नहीं करता। वो बालकां की नज़रां में नज़र मिलाकै बात नहीं कर सकता। ईमानदारी तैं उसनै कोय राम-राम भी ना करै। इतणा ए नहीं उसकी आपणी जिंदगी भी बिरान होज्या सै। दारू पीणे वाला तकरीबन जल्दी बीमार होसै। फेर वो घणे दिन नहीं पकड़ता।

-छबीले न्यू खोल थोड़ा होई थी अक तूं मनैं भाषण पिला दिए। एक घूंट लेण की इच्छा जताई थी, तनै तो मैं अपराधी ए डिक्लेर कर दिया। पर भाई एक बात बता। यो नशा इतणा खराब सै तो लोग पीवैं क्यूं सैं?

एक बात और, सुणा सै सरकार धोरै टैक्स चोखा कट्ठा होज्या सै। यू खर्च कित हो सै?

- भाई रसीले, देस-प्रदेश में हैल्थ सेंटर, पीएचसी, छोटे बड़े अस्पताल, स्कूल, कालेज, आईटीआई, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, एसडीएम कार्यालय, डीसी कार्यालय और सब क्याएं के बड़े-बड़े दफ्तर सैं। इनका खर्चा कड़े तैं आवै? और ये कई तरियां की पेंशन, फसल के रेट, मुआवजे और कई तरियां की स्कीम चला राखी सैं। जो आए महीने खात्यां में आवैं सैं। यू इतणा पीस्सा कड़े तैं आवै? सड़क, पुल, पीने का पानी, खेत का पानी, वगैरह वगैरह। खर्चा किस चीज में ना होता। किमे ये अलबादी लोग सरकारी संपत्ति नै नुकसान पहुंचाकै सरकार पै भार बढ़ा दे सैं। यो इतणा खर्चा कितोड़ तैं आवै?

आपणे तैं हिसाब ला ले, घर तैं लिकड़ते ही ढंग-ढंग पै पीस्से की जरुरत पड़े सै। इतणा पीस्सा सरकार कितोड़ तैं ल्यावै?

काम धंधे, कारोबार, बेच-खरीद इनपै टैक्स तो लाणा पड़े सै, इस्से तरियां दारू पै भी टैक्स लाया जा सै। और सुण, जै दारू पै रोक लगा भी दी तो पीणे वाले फेर भी लुक-छिपकै पीवैंगे, उननै चाहे दूसरे प्रदेशां तै ल्याकै पीणी पड़ो।

- हां छबीले, न्यू बी बतावैं सै अक दारू पीण आल्यां के शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होज्या सै। के बेरा कद कोरोना हमला बोल दे। बचकै रहणम ए भलाई सै।

- हां रसीले, सावधानी जरुरी सै। बाहर जावै तो मास्क लगाकै जाया कर। खाणे-पीणे का ध्यान रख और जाड्डे तै जरुर बचकै रहिये।

कोरोना इबै गया नहीं सै। न्यू कहा करैं जाड्डे तैं और ठाड्डे तैं बचकै रहणम ए फायदा सै। आच्छा मैं शहर में एक खास काम जा सूं। नए साल की राम राम।

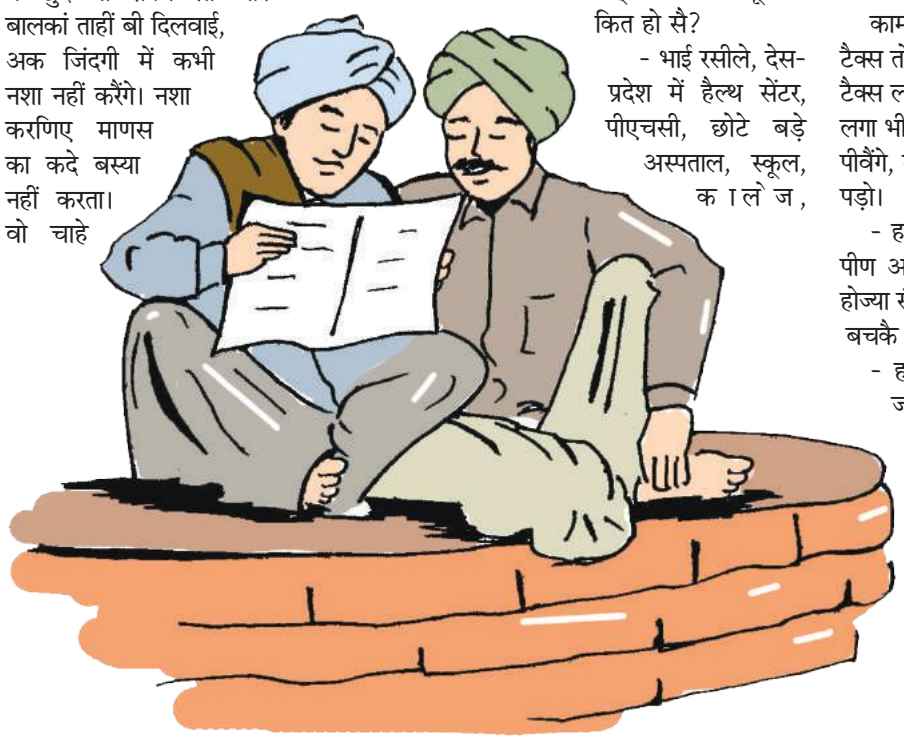

-मनोज प्रभाकर

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com